

सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 21-23 / 07 / 2026

मध्यप्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में तीन दिवसीय 21/07/2026 से दिनांक 23/07/2026 तक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम दिवस में मध्यप्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान के संचालक श्री प्रदीप वासुदेवा (भा.व.से.) के द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रायोजक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र.) म.प्र. भोपाल है। प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों के द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना से संबंधित विभिन्न विषयों पर PPT के माध्यम से जानकारी प्रदान की गयी। इसके उपरांत दिनांक 22 जुलाई 2026 को वन परिक्षेत्र निवास की ग्राम वन समिति मनेरी में सहभागी ग्रामीण समीक्षा (PRA) का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। विषय विशेषज्ञ श्री आर. बी. शर्मा (सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक), श्री ओंकार सिंह राणा (सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक) एवं श्री अभिषेक शर्मा के मार्गदर्शन में ग्रामीणों के साथ नजरी नक्शा, संसाधन चित्रण एवं समय चित्रण जैसी गतिविधियाँ कराई गई।

इस अवसर पर श्री आर. बी. शर्मा ने वन संरक्षण एवं प्रबंधन में जनभागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बिगड़े वनों के सुधार के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने लैंडस्केप एप्रोच की उपयोगिता बताते हुए कहा कि माइक्रोप्लान केवल वन विकास का दस्तावेज नहीं, बल्कि ग्राम स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक विकास का प्रभावी माध्यम भी है। उन्होंने वन समितियों के अभिलेख संधारण, पारदर्शिता, वार्षिक ऑडिट एवं नियमित अनुश्रवण को बेहतर वन प्रबंधन के लिए आवश्यक बताया।

कार्यक्रम के अंतिम दिवस प्रशिक्षार्थियों ने माइक्रोप्लान तैयार करने से जुड़ी समस्याओं पर विशेषज्ञों से चर्चा कर समाधान प्राप्त किया। समापन अवसर पर संस्थान के संचालक श्री प्रदीप वासुदेवा (भा.व.से.) ने विभिन्न वन मंडलों (दक्षिण बैतूल, रायसेन, उत्तर पन्ना, भिंड, हरदा, इंदौर एवं कटनी) से आए 33 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए एवं कार्यक्रम के अंत में मुख्य अन्वेषक डॉ. प्रतीक्षा चतुर्वेदी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस सफल आयोजन में संस्थान के श्री एस. एस. रघुवंशी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, डॉ. डी. के. कुलदीप, प्रियंका वर्मा, सोनल चतुर्वेदी, श्री सत्यम सक्सेना, श्री हिमांशु कुशवाहा, अजय लविशकर, विनीत मेहरा एवं श्री सिद्धार्थ पगारे आदि भी उपस्थित रहे।



नईदुनिया सिटी

जबलपुर



शुभ प्रभात

राष्ट्र की वायु गुणवत्ता

गुरुवार

पृष्ठ-10

पृष्ठ-25

48 36 29

(संकेत)

पृष्ठ-28

39 28 21

(संकेत)

पृष्ठ-21

19 15

(संकेत)

तीन दिवसीय प्रशिक्षण से वन प्रबंधन को मिलेगी नई दिशा, बनेगा संतुलन

एसएफआरआई में कार्यशाला का शुभारंभ, ग्राम विकास और जनसहभागिता पर जोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : वन क्षेत्रों के वैज्ञानिक, आकस्मिक-आधारित और स्थायी प्रबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य वन अनुसंधान संस्थान ने महाकुर्ण फल को है। संस्थान में बुधवार से शुरू हुए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न वन पट्टों के अधिकारियों और पैटर्न अगले को सूक्ष्म प्रबंधन योजना (माइक्रो प्लान) तैयार करने और उसके प्रभावों क्रियान्वयन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य वन संरक्षण, जीव विविधता संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को एकत्रित विकास माहौल से जोड़ना है। प्रशिक्षण का शुभारंभ संस्थान के संचालक प्रदीप

बासुदेवा बासे ने किया। उन्होंने कहा कि बदलते पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच वन संसाधनों का विज्ञानी एवं योजनाबद्ध प्रबंधन समय की आवश्यकता है। सूक्ष्म प्रबंधन योजना तकनीकी और दृष्टान्तव प्रामुक्त एवं मानव संसाधनों के अन्तर्गत पर आधारित विकास दस्तावेज है, जो क्वॉलिटी समुदायों की भागीदारी के साथ तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य वन संसाधनों का संतुलित एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करना, जीव विविधता का संरक्षण करना तथा



राज्य वन अनुसंधान संस्थान में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य व प्रतिनिधि। ● सौ. बासुदेवा बासे

जनसहभागिता आधारित वन प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से वन संरक्षण के साथ ग्रामीण आजीविका और सामाजिक विकास को भी पंजकुरी मिलती है। प्रशिक्षण में भोपाल से आए विषय विशेषतः आरबी शर्मा (सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक), ओंकार सिंह राणा (सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक) तथा अभिषेक शर्मा ने माइक्रो प्लान को अन्वेषण, निर्माण प्रक्रिया, पूर्व तैकरी और स्थायी ग्रामीण समीक्षा (पीआरए) जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी। संस्थान की मुख्य अन्वेषक डा. प्रतीक्षा चतुर्वेदी ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्य के लिए माइक्रो प्लान को उपयोगिता पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में वन मंडल दक्षिण बैतुल, रायसेन, टाटर पन्ना, भिंड, हरदा, इंदौर और कटनी से आए वन परिक्षेत्र अधिकारियों, वनपालों एवं वनरक्षकों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। प्रशिक्षण का उद्देश्य वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माइक्रोप्लान तैयार करने, डेटा संग्रहण तथा सहभागी ग्रामीण समीक्षा (पीआरए) की आधुनिक तकनीकों में दक्ष बनाना था, ताकि बिगड़े हुए वन क्षेत्रों के संरक्षण, संवर्धन और सतत विकास के लिए स्थानीय समुदायों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अन्वेषक डा. प्रतीक्षा चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्थान के एसएस रघुवंशी (वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी), डा. डीके कुलदीप, प्रियंका वर्मा, सोनल चतुर्वेदी, सत्यम सक्सेना, हिमांशु कुशवाहा, अजय लक्खर, विनीत मेहरा एवं सिद्धार्थ पगारे उपस्थित थे।

वन संरक्षण में जनभागीदारी सबसे जरूरी

मध्य राज्य वन अनुसंधान संस्थान में सूक्ष्म प्रबंधन योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान सूक्ष्म प्रबंधन योजना (माइक्रोप्लान) निर्माण पर आधारित तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हुआ। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि ग्राम स्तर पर स्थानीय समुदायों को साथ लेकर तैयार किए गए माइक्रोप्लान वन संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का भी सशक्त माध्यम बन सकते हैं। प्रतिभागियों ने निवास वन परिक्षेत्र के ग्राम मनेरी में आयोजित सहभागी ग्रामीण समीक्षा (पीआरए) गतिविधियों में भाग लेकर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिसमें एसडीओ अक्काशपुरी गोस्वामी, वन परिक्षेत्र अधिकारी मेघा पटेल एवं उनके वन अमले ने प्रतिभागियों को आवश्यक सहयोग एवं समन्वय उपलब्ध कराया।

विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया: प्रशिक्षण में भोपाल से आए विषय विशेषज्ञ आरबी शर्मा (सेवानिवृत्त



तीन दिवसीय प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। ● सौ. आरबी शर्मा (मुख्य वन संरक्षक), ओंकार सिंह राणा (सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक) तथा अभिषेक शर्मा ने ग्रामीणों के सहयोग से नजरी नक्शा, संसाधन मानचित्रण, समय चित्रण सहित सहभागी योजना निर्माण की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। अतिथियों ने बताया कि वन संरक्षण और प्रबंधन में जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण आधार है। बिगड़े हुए वन क्षेत्रों को पुनः समृद्ध बनाने में परिवर्तित करने के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। लैंडस्केप एप्रोच की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माइक्रोप्लान केवल वन विकास का दस्तावेज नहीं, बल्कि ग्राम स्तर पर समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने वन सभितियों में अभिलेख संधारण, पारदर्शिता, वार्षिक आडिट और ग्राम सहभागिता को सुदृढ़ वन प्रबंधन की आधारशिला बताया।

व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा: समापन सत्र में प्रतिभागियों ने माइक्रोप्लान तैयार करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर विशेषज्ञों से चर्चा कर समाधान प्राप्त किए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर संस्थान के संचालक प्रदीप बासुदेवा (भावसे) ने दक्षिण बैतुल, रायसेन, उत्तर पन्ना, भिंड, हरदा, इंदौर एवं कटनी वनमंडलों से आए 33 वन परिक्षेत्र अधिकारियों, वनपालों एवं वनरक्षकों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए। प्रशिक्षण का उद्देश्य वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माइक्रोप्लान तैयार करने, डेटा संग्रहण तथा सहभागी ग्रामीण समीक्षा (पीआरए) की आधुनिक तकनीकों में दक्ष बनाना था, ताकि बिगड़े हुए वन क्षेत्रों के संरक्षण, संवर्धन और सतत विकास के लिए स्थानीय समुदायों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अन्वेषक डा. प्रतीक्षा चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्थान के एसएस रघुवंशी (वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी), डा. डीके कुलदीप, प्रियंका वर्मा, सोनल चतुर्वेदी, सत्यम सक्सेना, हिमांशु कुशवाहा, अजय लक्खर, विनीत मेहरा एवं सिद्धार्थ पगारे उपस्थित थे।